राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 3 ■ अंक 10 ■ फरवरी 2020 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

सशक्त महिला सशक्त भारत

परिषद गतिविधियां

राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा प्रकाशित 'भारतीय चिति और गांधी चिन्तन' पुस्तक का लोकार्पण करते अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, रा. अध्यक्ष डॉ. एस. सुबैय्या और रा. महामंत्री निधि त्रिपाठी

लखनऊ : युवा उत्सव के प्रतिभागियों को सम्मानित करते अभाविप के अवध प्रांत अध्यक्ष डॉ. सर्वेश सिंह, उ. प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री राहुल बाल्मीकि, प्रदेश मंत्री अंकित शुक्ला व अन्य

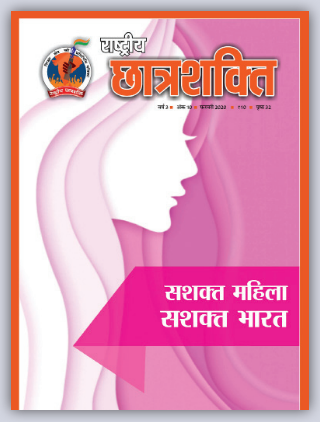

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 3, अंक 10
फरवरी, 2020

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 **अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचाने भारतीय नारी**

कोई भी युग उज्जवल बना है तो वह नारी शक्ति की पवित्र निर्मल प्रभा से और कलह का बवंडर उठा है तो वह भी नारी विकृति के...

संपादकीय 04
अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तथा महिला... 08
अभाविप ने किया गुज्जर बकरवाल समाज सम्मेलन का आयोजन 10
अभाविप की दो दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति बैठक गोरखपुर में संपन्न 11
शिक्षा बजट 2020 : महत्वकांक्षी भारत की झलक 12
अभाविप ने आयोजित किया 'रन फॉर नेशन' मैराथन 15
बेजा विरोध का दि'शाहीन बाग 16
अलीगढ़ : अभाविप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 18
REGIONAL LANGUAGE MUST BE PROMOTED FOR TAKING THE EDUCATION TO GRASS ROUTE LEVEL : SUNIL AMBEKAR 19
पीएफआई – आतंक का नया प्रारूप 20
DISSECTION OF PAK'S FRUSTRATION 22
पीढियां प्रेरणा प्राप्त करेंगी पूज्य दतोपंथ ठेंगड़ी जी से 24
पूर्वोत्तर में शांति का मार्ग प्रशस्त : बोडो समझौता 26
लखनऊ : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा युवा उत्सव का आयोजन 28
निर्भया कांड के दोषियों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर फांसी टालने की घटना क्या त्वरित संवैधानिक सुधारों की मांग करती है? 29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

दिल्ली में एक बार पुन: अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने जा रहे हैं। परिणाम आने के बाद उन्होंने टिप्पणी की कि देश की राजनीति एक नये दौर में प्रवेश कर चुकी है। कुछ हद तक यह बात सच भी मालूम होती है।

इस परिणाम में भाजपा के घोषित उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की पुन: पुष्टि हुई है वहीं अपने अप्रासंगिक होने का उत्सव मनाते हुए कांग्रेस के चिदंबरम और दिग्विजय सिंह सरीखे नेता केजरीवाल की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के वारिस होने का दावा करने वाला राजनैतिक दल जब इस प्रकार की अघोर साधना में जुट जाये और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिये क्षेत्रीय दलों की ओर निहारे तो सच में यह राजनीति के एक नये दौर के आने का संकेत है।

राजनीति का यह नया दौर किसी सकारात्मकता का नहीं बल्कि निष्क्रियता और नकारात्मकता की वजह से आता दिख रहा है। निहित राजनैतिक स्वार्थों के लिये राष्ट्रीय मुद्दों पर विकृत बहस चलाना और अंतत: समाज में भ्रम का वातावरण तैयार कर स्वयं के अस्तित्व को दाँव पर लगा कर किसी और की उपलब्धियों पर खुद को शाबाशी देने का जो करतब कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं वह उनकी दयनीय मनोदशा का ही प्रमाण है।

स्थानीय चुनावों में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के ऊपर बिजली–सड़क–पानी का सवाल हावी होता है, यह बार–बार का अनुभव है। विकास की तुलना में मुफ्तखोरी भारी पड़ती है, यह भी सिद्ध है। केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि को इस जीत का आधार बताया। किन्तु जिन इलाकों में विकास का यह दौर सबसे कम पहुंचा वहाँ आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत होना इस दावे पर सवाल ही नही खड़े करता बल्कि तस्वीर के दूसरे पहलू की ओर भी देखने का अवसर देता है।

मुस्तफाबाद और शाहीन बाग में भाजपा प्रत्याशी को किसी राउंड में पाँच और उसी मे आप प्रत्याशी को सात हजार वोट मिलना यह बताता है कि यह आंधी विकास की नहीं बल्कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कर वोट बैंक की फसल काटने की रणनीतिक सफलता है। यह प्रारंभिक संकेतों के आधार पर कहा जा रहा है किन्तु चुनावी विशेषज्ञों की यह जिम्मेदारी है कि विष्लेषण में यह पैटर्न दिखाई देता है तो बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष इसे उठाया जाय। इसे दलगत राजनीति की गिरावट के रूप में ही नहीं बल्कि भविष्य की चुनौती के रूप में भी देखे जाने की आवश्यकता है।

सकारात्मक रूप से सोचें तो केजरीवाल की सत्ता में वापसी विकास के उन्हीं मुद्दों के इर्द–गिर्द अपने चुनावी अभियान को केन्दित रखने के कारण हुई है जिन्हें लेकर केन्द्र की मोदी सरकार बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने में दिल्ली सरकार कितना सफल रही है, यह तो पड़ताल का विषय है, किन्तु वह इसे विमर्श के केन्द्र में रखने में अवश्य सफल हुई है। केन्द्र सरकार के साथ इस मामले कोई तुलना अथवा प्रतियोगिता तो संभव नहीं है, किन्तु इन मुद्दों पर साथ कदम बढाने का तय करके विकास की गति को तेज अवश्य किया जा सकता है जो समय की माँग है।

वासंती वातावरण में आने वाले होली के पर्व को मतभेद भुला कर नयी पहल के अवसर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह राजनैतिक स्तर पर भी हो, शाहीन बाग में भी हो, कश्मीर में भी हो और जेएनयू और एएमयू में भी। अंतत: हम सबकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं एक ही हैं और आगे बढ़ने का सपना भी।

भवदीय

संपादक

अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचाने भारतीय नारी

| विनीता इंदवार |

कोई भी युग उज्ज्वल बना है तो वह नारी शक्ति की पवित्र निर्मल प्रभा से और कलह का बवंडर उठा है तो वह भी नारी विकृति के गहन अंधकार से । इस देश की नारीशक्ति को पाश्चात्य शैली में ढालने तथा उसको उस दृष्टि से जाग्रत करने के अनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं । किन्तु मुझे लगता है कि भारत की नारी शक्ति अगर हमारे देश की पवित्र परंपराओं, मान्यताओं तथा गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित होगी तो वह स्वयं गौरव एवं स्वाभिमान का अनुभव करेगी । इसके साथ - साथ वह यह भी अनुभव करेगी कि पवित्र संस्कृति व परंपराओं की भूमि भारत में जन्म लिया है । वह अनुभव करेगी कि इतिहास में कभी भोग्या नहीं समझा गया। किन्तु आज मानव अपने जीवन के विभिन्न क्षणों को स्त्री भोग्या बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नारी शक्ति को पीछे धकेलने के प्रयत्न विभिन्न प्रकार से किये जा रहे हैं। धीरे - धीरे हम नारी अपनी गरिमा को, अपने गौरव को तथा अपनी वीरता को भूलते जा रहे हैं परिणामस्वरूप आज भारतीय स्त्री को विज्ञापन के रूप में सजाकर बाजार में प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई स्वीकार करे या न करे किन्तु हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं। उसके प्रति आकर्षण के कारण हम अपने 'स्व' को ही भूल गए। हम नारी एक ऐसी पवित्र शक्ति है जो अपने प्रारंभिक काल से वृद्धावस्था तक पुत्री, बहन, माता, पत्नी, सास

आदि के रूप में रिश्ता निभाते हैं । हम महिला 'माँ' हैं। हम 9 महीने तक शिशु को अपनी कोख में रखकर जन्म देते हैं जिनकी कोख से भारत के वीर भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, भगवान बिरसा मुंडा जैसों ने जन्म लिया। मैं सभी महिलाओं /छात्राओं से आह्वान करती हूं कि बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनो, रानी पद्मावती बनो, सिनगी दई, फूलो - झानो बनो । यदि माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो यशोदा और जीजाबाई जैसी माँ बनो। मेरी बहनों आप अपनी अर्थ को समझो, उसी में आपका और समग्र भारत का कल्याण है।

कभी - कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हम कैसी विचित्र दासतां और गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं। हमें अपनी क्षमता पर और अपने आप पर गौरव का अनुभव नहीं होता। हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रखते। भगवान ने हम नारी को कितना उच्च स्थान दिया है। लोग मुझे कहते हैं बहन छात्राओं के लिए कुछ ऐसा करो जिससे वह पुरुषों से आगे निकल जाएं। किन्तु ये बात मुर्खों वाली है क्योंकि जिस नारी को ईश्वर ने सर्वोच्च स्थान दिया है उसे पुरूषों के समकक्ष क्यों खड़ा करें। बस ! नारी को अपने आप पर गर्व हो जाए कि हम वही नारी हैं जो (रानी लक्ष्मीबाई) भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय संस्कृति ही तो हम बहनों को हमारी महानता से साक्षात्कार कराती है। अतः हम अपने जीवन पर कभी भी पश्चिमी सभ्यता की धूल न जमने दें।

लोग कहते हैं कि स्त्री तो ममता की मूर्ति है। ममता को सीने से लगाए रखती है। लेकिन लक्ष्मीबाई ने दिखा दिया कि जब समय उसे आह्वान करता है, काल उसे ललकारता है तो स्त्री ममता को सीने से लगाए बैठी नहीं रहती बल्कि उसे पीठ में बाँधकर हाथ में शौर्य की तलवार लेकर दुश्मनों का सीना चीरने निकल पड़ती है।

इन्हीं सब विचारों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है) ने छात्राओं को उनके अंदर बसी हुई नारी शक्ति को पुनः जाग्रित करने के लिए मिशन साहसी लाया। आज जो महिलाएं/छात्राएं देहात्मभा लिए फैशन की दुनिया में है, वे दिखावे की जिंदगी जी रही है। अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलती जा रही है। इसलिए जब हम बहनों

के साथ गलत होता है तो हम डरी सहमी सी रहते हैं। हमारे साथ गलत करने वालों का न हम विरोध कर पाते हैं और न ही उनसे लड़ पाते हैं । बहनों की इसी स्थिति को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारत वर्ष के शैक्षिक परिसरों में मिशन साहसी का कार्यक्रम चला रहा है। मिशन साहसी के द्वारा पूरे देश भर में लगभग 7.5 लाख से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा के विभिन्न तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है छात्राओं को निडर, निर्भय व स्वावलंबी बनाना। इस मिशन साहसी के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने महिलाओं को उनकी वीरता, शक्ति व महत्ता को पुनः जाग्रत करने करने का कार्य कर रहा है। अभाविप ने इस अभियान के द्वारा महिलाओं व छात्राओं को अनुभूति करा दी है कि वे भी रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है । यदि ममता की मूरत बनकर शांत रहती है तो समय आने पर सिनगी दई, रानी गाईदिनल्यू, और रणचंडी भी बन सकती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे देश भर में सभी प्रांतों में छात्राओं के बीच कार्य बढ़ा है। तभी तो पूरे भारत में लगभग 65 छात्राएं भारत की ऐतिहासिक गौरव तथा सभ्यता व संस्कृति की रक्षा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रविरोधी संगठन को समाप्त करने के लिए गृह त्याग कर पूर्णकालिक हो गई है। अभाविप का उद्देश्य है कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण के लिए सर्वप्रथम व्यक्तित्व का निर्माण जरूरी है। अभाविप अपने राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर कार्य करती है। देश के प्रगति के मार्ग को रोकने वाली जितनी भी समस्याएं हो, उसके समाधाने के लिए परिषद के कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी विचार रखने वाली छात्र संगठन के साथ जुड़कर यदि कोई छात्रा पूर्णकालिक होकर अथवा पूरे मन से देश के लिए कार्य करती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही तो व्यक्तित्व निर्माण है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 09 जुलाई 1949 को विधिवत रूप से एक छात्र संगठन के रूप में पंजीकृत हुआ। अभाविप ने अपने स्थापना काल से ही छात्राओं को एक छोटे इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सदैव नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जैसे छात्रा कार्यकर्ता है। महिला शिक्षा की बात की जाए या उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, कन्या भ्रूण हत्या अथवा उनके स्वावलंबन की बात की जाए। इन सभी क्षेत्रों में अभाविप ध्यान देकर कार्य कर रही है। आज हम देखते हैं कि देश में घटित विभिन्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर अभाविप आंदोलन करती है, जिसमें छात्राएं भी बढ़ - चढ़कर हिस्सा लेती है तथा इन आंदोलनों का नेतृत्व भी करती है।

महिला शिक्षा की बात की जाए या उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, कन्या भ्रूण हत्या रोकने अथवा उनके स्वावलंबन की बात की जाए। इन सभी क्षेत्रों में अभाविप ध्यान देकर कार्य कर रही है। आज हम देखते हैं कि देश में घटित विभिध्न मुद्दों व समस्याओं को लेकर अभाविप आंदोलन करती है, जिसमें छात्राएं भी बढ़ - चढ़कर हिस्सा लेती है तथा इन आंदोलनों का नेतृत्व भी करती है।

मैं स्वयं एक छात्रा कार्यकर्ता हूं और मैं सभी बहनों से कहती हूं कि अपनी संस्कृति को जानों। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और राष्ट्रवादी विचारधारा को मन में रखकर सेवाभाव से कार्य करो। पाश्चात्य संस्कृति में मत जाओ। स्वामी विवेकानंद जी के एक उपदेश पर प्रत्येक बहन को कम - से - कम एक बार जरूर चिंतन करनी चाहिए कि नकल संस्कृति की धरोहर कभी भी नहीं बन सकती। राजा की वेशभूषा धारण कर लेने से कोई राजा नहीं बन जाएगा। नकल के द्वारा कभी भी प्रगति नहीं किया जा सकती। इसलिए बहनों आप स्वावलंबी बनो। हम बहनें ही विश्व के मानव की नैतिक आदर्शों की आधारशिला हैं। इस प्रकार सारा समाज बड़ी - बड़ी मुश्किलों के सामने उठकर खड़ा हो सकता है। बस केवल इतना याद रहे कि हम इस महान भारतवर्ष की धरोहर हैं, रीढ़ हैं, हम स्वयं ही भारत माता है। ■

(लेखक अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री हैं।)

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तथा महिला...

। **मनीषा कोठेकर** ।

आज विश्व में महिलाओं की स्थिति के बारे मेंजो चिंतन तथा अध्ययन की स्थिति है वह लगातार वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रयासों का परिणाम हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। विश्व में लगभग हर देश के द्वारा 8 मार्च को अंतर-राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1910 में अंतर राष्ट्रीय परिषद में जर्मन कम्यूनिष्ट नेता क्लरा झेटकिन ने इस दिन को अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा की, जिसके बादबाद यह दिन जागतिक महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्लरा झेटकीन के द्वारा इसी दिन को चुनने के पीछे इतिहास छिपा हुआ है। 8 मार्च 1857 में न्यूयार्क में 'कपड़ा तथा वस्त्रोद्योग ' में काम करने वाले कामकाजी महिलाओं ने उनकी मांग के लिए बड़ी संख्या में आंदोलन किया, जुलूस निकाला गया। उनकी मांगे थी 'समान वेतन तथा समान कार्य संस्कृति'। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यह आंदोलन की बड़ी चर्चा हुई। क्लरा झेटकीन एक कम्युनिष्ट नेता थे जिस कारण उन्होंने इसी दिन को चुना और 1910 के जागतिक परिषद में वह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

1910 की यह परिषद दूसरी महिला परिषद थी। इसके पहले 1907 में यूरोप में स्टुटगार्ड में 'अंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद' का आयोजन हुआ था,जिसमें 15 देशों से महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। जिसमें भारत से 'मैडम कामा' उपस्थित थी। 'मैडम भीकाजी कामा' ने वहां पर उपस्थित सभी को 'भगिनीभाव''Sisterhood' पालन करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद द्वितीय महायुद्ध के कारण इस आंदोलन की गति मंद हो गई। फिर 60 के दशक में स्त्री आंदोलन ने जोर पकड़ा और धीरे-धीरे 'महिला दिन' का महत्व भी बढ़ते गया।

जैसा हम सब जानते हैं कि भारत के मुक्ती संग्राम में महिलाओं का सहभाग बहुत बड़ी संख्या में थी, साथ ही स्त्री मुक्ती आंदोलन भी चला। सामाजिक विषयों के साथ ही महिला अपने स्थिति तथा अधिकारों के प्रति भी सजग हुई। परिणामतः पूरे भारत में छोटे-छोटे तौर पर महिलाओं के गुट बने, संस्थाओं का जन्म हुआ। 1927 में मार्गारेट कूझीन ने 'ऑल इंडिया वूमेन्स एसोसिएशन ' की स्थापना की। 1936 में 'राष्ट्र सेविका समिति' का जन्म हुआ। 1918-22 तक डॉ. ऐनीबेसेंट

द्वारा 'मताधिकार आंदोलन' चलता रहा और 1947 के दरम्यान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटीय प्रोवीन्स पेशावर में मुस्लिम महिलाएं मताधिकार के मांग को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित हुई। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में महिलाओं का मताधिकार तथा चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार प्राप्त होने हुआ।

महिलाओं ने विभिन्न आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया जैसे महाराष्ट्र में 1940-48 के दरम्यान साठ कपड़ा मीलों के आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया तो बंगाल प्रांत में 1944 में भाग लिया, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व 'बारमानी' नामक प्रसिद्ध महिला ने किया।

1947 में स्वातंत्र्य के साथ हुये बंटवारा से जो हिंसाचार हुआ उसके बाद पीड़ितों के मदद कार्य में महिलाओं का बड़ा सहभाग रहा। इस प्रकार अनेक सामाजिक आंदोलनों में वह सक्रिय रही परंतु राजकीय क्षेत्र में उसका सहभाग कम रहा। 1952-71 में लोकसभा में मतदान का प्रतिशत 45 था जिसमें महिला 27 प्रतिशत थीं। आज 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में उनकी उपस्थिति तथा कार्य लक्षणीय है अपितु लोकसभा तथा राज्यसभा में आज भी प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है।

1960 के अंत में कई सारे सामाजिक विषयों के आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया चाहे वह 'शहिदा मिल' आंदोलन हो या 'चिपको' आंदोलन हो। इसके सहभाग से महिलाओं के अपनी समस्याओं तरफ ध्यान केन्द्रीत होने लगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने 'शराब बंदी' आंदोलन चलाया।

1972 में गुजरात में इरन भट्ट ने असंगठित क्षेत्र के कामकाजी महिलाओं को एकत्रित किया व SEWA नाम का संगठन बनाया और फिर यह अन्य राज्यों में भी फैलता गया। 1974 में 'समानता की ओर' यह रिपोर्ट प्रसिद्ध हुआ जो महिलाओं के स्थिति को तथा उनकी मांगों को उजागर कर रहा था।

1975 में उन्होंने यह वर्ष, महिला वर्ष तथा बाद में 1975-1985 यह 'महिला दशक' नाम से घोषित किया और 1975 के महिला वर्ष को सम्मानित करने के लिए 'मैक्सिको सिटी' में प्रथम 'जागतिक महिला परिषद' का आयोजन किया गया इसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था। इसके बाद 1980 में कोपनहेन में, 1985 में नैरोबी में तथा 1995 में बीजिंग में जागतिक महिला परिषदों का आयोजन हुआ। इन चार महिला परिषदों के साथ बीच-बीच में तथा 1995 में बीजिंग के बाद हर पांच साल में छोटी-छोटी परिषदों होती गयी। जिनमें महिलाओं के विभिन्न विषयों पर चिंतन, चर्चा, अध्ययन चलें। इनमें सम्मिलित सभी देशों में के द्वारा परिषद में जो निर्णय लिये गये उनके अनुसार विविध कार्यक्रम चले, योजनाएं बनी।

भारत ने भी इसे स्वीकार किया गया। 1980 में भारत में 'राष्ट्रीय महिला दिवस' की स्थापना की गयी। 1977-80 में जो दहेज विरोधी आंदोलन के परिणामस्वरूप 1983-86 के दरम्यान इनके कानूनों में संशोधन हुए। 1978 में हैदराबाद में 'हमीजाबी', 1980 में मथुरा बलात्कार की बहुत चर्चा हुई, उसको लेकर हर स्थान पर आंदोलन चले परिणामतः 1983 में बलात्कार के संबंध में कानून बना। 1986-87 को दरम्यान कर्नाटक में 'स्वयं सहायता समूह' की स्थापना हुई और पूरे भारत में इसका फैलाव होने लगा। आज 'स्वयं सहायता समूह' के माध्यमों से न केवल महिला अपितु परिवार सशक्त तथा आत्मनिर्भर होते दिखाई दे रहे हैं।

1993 में देश में संविधान में संशोधन होकर महिलाओं को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ जो आगे चलकर 50 प्रतिशत हुआ। इससे महिलाएं बड़ी संख्या में विविध स्थानों पर काम करने में जुट गई, उनका निर्णय प्रक्रिया में सीधा सहभाग होने लगा, परिणामस्वरूप कई विकास के अछूते मुद्दे आज प्रमुखता से सामने आये हैं। 1992 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' तथा बाद में 'राज्य महिला आयोग' स्थापित हुए। जिसके कारण महिलाओं को अपनी मांगे रखने के लिए मंच मिला। इसके तहत महिलाओं की समस्याओं के बारे में कई अध्ययन होते गये और उनके आधार पर महिलाओं के लिए कौन से कार्यक्रम किस प्रकार चलने चाहिये। इसके बारे में शासन को मार्गदर्शन मिलता था।

2001 में 'राष्ट्रीय महिला नीति' बनी, इसमें भारतीय महिलाओं के स्थिति का जायजा लिया गया तथा उनके लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के साथ 'महिला सुरक्षा' विषय भी गंभीरता से लिया गया और उसके लिए विविध

कार्यक्रम,कानून बनाये गये। जिसमें 'घरेलु हिंसाचार' तथा 'काम के स्थान पर लैंगिक अत्याचार' के विरोध में कानून बने। दिल्ली में 'निर्भया' कांड के बाद में बलात्कार विषयक कानून में संशोधन हुए, इनमें आहत महिलाओं को मदद का प्रावधान बना, एसिड अटैक को भी गंभीरता से लिया गया और उनमें प्रताड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किये गये।

शिक्षा के क्षेत्र में 'महिला शिक्षा' को लेकर काफी काम हुआ है। 1851 में जब महात्मा तथा सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली, उस समय के महिला शिक्षा की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन-आसपास का फर्क है। यह लगातार इस दिशा में किये गये प्रयासों का नतीजा है। 1961 में महर्षी कर्वे ने पहला महिला विश्वविद्यालय शुरू किया। आज कई सारे 'महिला विश्वविद्यालय' हम भारत के विभिन्न स्थान पर चलते हुए देखते है। लड़कियों के अलग विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के साथ सह शिक्षा में भी प्रतिशत बढ़ा है। देश को जब स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ तो लड़कियों को शिक्षा में प्रमाण 0.69 प्रतिशत था जो आज 60 प्रतिशत के करीब है। सभी प्रकार के उच्च शिक्षा में, तकनीकों तथा व्यावसायिक शिक्षों में भी उनका प्रमाण तथा सहभाग सराहनीय है। सॉफ्टवेअर क्षेत्र जो नॉलेज इंडस्ट्री कहा जाता है, उसमें भी उनका प्रमाण लगातार बढ़ रहा है। 2004 में जहां पुरूषों का प्रमाण इसमें 76 प्रतिशत था महिलाएं, 24 प्रतिशत थी, 2007 में पुरूषों का 65 प्रतिशत तथा महिलाएं 35 प्रतिशत थी और आज वह 50 प्रतिशत से भी अधिक दिखाई देता है। विज्ञान, तंत्रविज्ञान, संशोधन के क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे आ रही है।

यह महिलाओं के प्रगति का चित्र मनको आनंद देने वाला है। साथ में उनमें सामने अनेक चुनौतियां भी है, अनेविध समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में इनको देखना, परखना तथा उनको सुलझाने के लिए सही मार्ग को खोजना आवश्यक है। महिलाएं हर क्षेत्र के योग्य तथा उचित सहभाग से ही देश के हर क्षेत्र का विकास संभव है। यह विकास सबके साथ तथा सबके सहभाग से साथ ही सभी के विकास को सामने रखकर करने से सही अर्थ में देश का विकास होगा। आनेवाले 8 मार्च 2020 के 'जागतिक महिला दिन' को इसी कामना के साथ आपको हार्दिक शुभकामना। ■

(लेखिका भारतीय स्त्री शक्ति से संबद्ध हैं।)

अभाविप ने किया गुज्जर बकरवाल समाज सम्मेलन का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जम्मू – कश्मीर प्रांत द्वारा विशेष संपर्क अभियान के तहत गुजर बकरवाल समाज सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। आयोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर अपने संबोधन में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए सजग समाज को सम्मान मिलना चाहिए। गुज्जर समाज हमेशा देश की एकता एवं अखंडता के लिए खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी कभी गुज्जर छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में कोई परेशानी आएगी तो विद्यार्थी परिषद उस समस्या को हल करने के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी।

सरपंच सिराज उद दीन ने गुज्जर समाज को आ रही समस्याओं से उपस्थित लोगों को परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि हमलोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, घास के बने कुलों में रहते हैं। मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्यालय होने की जरूरत बतायी। साथ ही धैर्य से उनकी बातों को सुनने के लिए सभी धन्यवाद भी दिया।

वहीं मौला अब्दुल गफ्फार ने कहा कि हम गुज्जर हमेशा से ही हिन्दुस्तान की सरजमीं के लिए वफादार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए हमें जान भीं गंवाना पड़े तो कोई गम नहीं। गुज्जर नेता लियाकत अली एवं छात्राओं ने मौके पर पीआर गौजरी गीत भी गाया।

सम्मेलन में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, सरपंच सिराज उद दीन, सरपंच लियाकत हुसैन, युवा गुज्जर नेता लियाकत अली, मौलाना अब्दुल प्रमुख रूप उपस्थित थे। ■

अभाविप की दो दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति बैठक गोरखपुर में संपन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दो दिवसीय बैठक (25 -27 जनवरी, 2020) का आयोजन किया गया था। जानकारी के मुताबिक बैठक में शिक्षा, महिला सुरक्षा, अधिवेशन में पारित प्रस्ताव, नागरिकता संशोधन एक्ट पर मंथन हुआ। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस सुबैय्या ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश में राष्ट्र हित के विचारों को लेकर अपनी सक्रियता बनाए रखती है। आज जिस प्रकार का राष्ट्रविरोधी माहौल देशभर में फैलाया जा रहा है, विद्यार्थी परिषद ऐसी गतिविधियों से समाज को कतई प्रभावित नहीं होने देगी।

वहीं अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो छात्र हित, देश हित व समाज हित की मात्र बात ही नहीं करता अपितु उसके लिए प्रयास भी करता है व सफल भी होता है। आज देश में ऐसे कुछ छात्र संगठन है जो देश के लिए समस्या बन रहे हैं वहीं परिषद उन समस्याओं का समाधान बन रहा है। आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों से प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने पर तमाम संगठन देश को भ्रमित करने का काम रहे हैं, शाहीन बाग में धरने पर बैठकर देशभर में झूठ फैला रहे हैं, वहीं परिषद के जम्मू प्रांत ने ऐसे भ्रमित लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वहां प्रबुद्ध लोगों के साथ- साथ मदरसों तक में जाकर परिषद कार्यकर्ता विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। जेएनयू में छात्र हित के नाम पर देश विरोधी प्रोपेगंडा चलाने वाले छात्र संगठन छात्र हित हेतु कोई काम न करते हुए देश को बरगलाने का काम कर रहेहैं। कुछ मीडिया के लोग भी हैं जो अभाविप के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर स्टिंग ऑपरेशन करते हैं जो कि बाद में फर्जी पाया जाता है। आज देश में महिलाओं के साथ शोषण अपराध को देखते हुए विद्यार्थी परिषद महिला सुरक्षा को लेकर गत वर्ष से ही मिशन साहसी नामक अभियान चला रही है जिसके माध्यम से छात्राओं को शैक्षणिक परिसरों में आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। हिमाचल प्रांत द्वारा इस वर्ष वातावरण को शुद्ध रखने हेतु व समाज को इसके प्रति जागरूक रखने हेतु 8 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

'भारतीय चिति और गांधी चिंतन' पुस्तक का लोकार्पण

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक में राष्ट्रीय छात्रशक्ति द्वारा प्रकाशित भारतीय चिति और गांधी चिंतन पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक गांधी जी के सार्धशती के उपलक्ष्य पर प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गांधी जी से जुड़े हुए कई अनछुए पहलुओं को उजागर करने का काम किया गया है, जिसमें ग्राम स्वराज, स्वदेशी, सनातन धर्म, गाय को लेकर गांधी जी के विचार इत्यादि शामिल है। पुस्तक का लोकापर्ण अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुबैय्या, महामंत्री निधि त्रिपाठी और संगठन मंत्री आशीष चौहान ने किया। पुस्तक के बारे में अभाविप के बारे में बताते हुए परिषद के पदाधिकारियों ने कहा पुस्तक में गांधी जी से जुड़े उन विषयों को उठाने की कोशिश की गई है जिससे अधिकांश लोग अनजान है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्यसमिति बैठक का आयोजन गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अमृता कला वीथिका सभागार में किया गया था। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुब्बया, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी व राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। दो दिन तक चले इस बैठक में अभाविप के कार्यों एवं आगामी योजना समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, पूर्व राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, जी लक्ष्मण, प्रफुल्ल आकांत, अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख श्रीहरि बोरिकर, अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं प्रकाशन प्रमुख मनोज कांत सहित देशभर के कुल 87 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ■

शिक्षा बजट 2020 : महत्वकांक्षी भारत की झलक

| अभिषेक रंजन |

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के समावेशी विकास के लिए कई विशेष पहल करने का प्रस्ताव 1 फरवरी 2020 के अपने बजट भाषण में देश के सम्मुख रखा। अपने 161 मिनट के बजट भाषण में शिक्षा सहित देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास की योजना और आर्थिक लेखा-जोखा शामिल था।

शिक्षा बजट

बजट प्रावधान की बात करें तो इस वर्ष शिक्षा बजट में न केवल बढ़ोतरी हुई है बल्कि यह अब तक का सर्वाधिक शिक्षा बजट भी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय बजट में 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए गए है। बजट में जहाँ स्कूली शिक्षा के लिए 59,845 करोड़, वही उच्च शिक्षा के लिए 39,467 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्किल डेवेलपमेंट के लिए भी 3 हजार करोड़ अलग से आवंटित किए हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014-15 में शिक्षा पर कुल खर्च 2.8 प्रतिशत था, अभी 2019-20 में बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया है। अगर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर हो रहे कुल खर्च की बात करें तो वर्ष 2014-15 में शिक्षा पर जहाँ 3.54 लाख करोड़ खर्च हो रहा था, 2019-20 में यह बढ़कर 6.43 लाख करोड़ हो गया है। राज्य व केंद्र के कुल बजटीय व्यय के हिसाब से देखें तो यह 10 प्रतिशत से भी अधिक है। वर्ष 2019-20 में देश भर में कुल बजटीय व्यय 60.72 लाख करोड़ था।

शिक्षा संवैधानिक रूप से राज्य और केंद्र दोनों के जिम्मे आता है। केंद्र नीतिगत निर्णयों, समग्र शिक्षा, मिड-डे मील जैसी केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय जैसे स्कूल चलाने पर ही विशेष खर्च करती है. उसी तरह केंद्र सरकार का ज्यादातर पैसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मुहैया कराने पर ही खर्च होता है। लेकिन देश की एक बड़ी आबादी राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे स्कूल, कॉलेजों में पढ़ती है, जिस पर राज्य ही पैसे खर्च करते हैं, कई केन्द्रीय योजनाओं में राज्य साझीदार भी रहता है।

नई शिक्षा नीति

बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं आने वाले समय में भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने वाली होंगी। विशेष तौर से नई शिक्षा नीति लागू करने की बात वित्त मंत्री ने कही। 2030 तक जब विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी भारत में होगी, देश और दुनिया की आवश्यकता को समझ सकने वाली भारत की शिक्षा नीति बने, इसकी नितांत जरुरत है। सरकार ने वैज्ञानिक एस. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो शिक्षा समिति बनाई थी, उसके लिए देशभर से लाखों सुझाव आए। सरकार इन सुझावों को इकठ्ठा कर जल्द देश के हित में बेहतर शिक्षा नीति लागू करे, इस बात का इंतजार पूरा देश कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले अकादमिक सत्र से नई शिक्षा नीति अमल में लाई भी जायेगी।

शिक्षा क्षेत्र में निवेश

शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के अलावा एफडीआई के रास्ते को भी अपनाने की बात की है, ताकि प्रतिभाशाली शिक्षकों, नवाचारी प्रयोगों, बेहतर प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक पैसे की कमी को पूरी की जा सके।

भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक बड़ी धनराशि वैश्विक संस्थाओं से ही मिलती है। खासकर सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से ही शुरु हो सके थे । विश्व बैंक ने भारत

में 2003 में शुरू हुए सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता दी थी। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत हर बच्चे की प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर इसे बुनियादी अधिकार बना दिया था। इस कार्यक्रम की वजह से 2.06 लाख प्राइमरी और 1.61 लाख अपर प्राइमरी स्कूल खुले। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2001 में 3.2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर थे, इनकी संख्या 2012-13 तक घटकर लगभग 30 लाख पर पहुँच गयी।

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक संस्थाएं विकसित हों, इस प्रयोजन से हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) नाम की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाई गयी है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी संस्थाओं को आधारभूत संरचना के विकास के लिए लोन देने के लिए बनाया गया है। बजट में उसके फंड में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ये 100 करोड़ से बढ़कर 2,200 करोड़ हो गया है। इसके बावजूद पैसे की कमी से शैक्षणिक संस्थाएं प्रभावित न हों, सरकार ने विदेशी निवेशकों और संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। इस कदम से उच्च शिक्षा, विशेषकर सूचना-तकनीक के साथ- साथ मॉडर्न साइंस से जुड़े शोध कार्यों में भारत को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

वित्तीय अभाव में देश की प्रतिभा दम न तोड़े, इस बात की चिंता तो देश को करनी ही चाहिए ताकि देश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ यह ध्यान भी रखना होगा कि वैश्विक बिरादरी से सहयोग भारत की जरुरतों और भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाए।

रोजगारपरक शिक्षा

स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से 3 हजार करोड़ देने के साथ-साथ सरकार ने रोजगारपरक शिक्षा की दिशा में भी प्रयास करने की बात बजट के जरिये बताई है। रोजगारपरक शिक्षा वर्तमान समय की जरुरत भी बनती जा रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़ दें तो सामान्य डिग्री, डिप्लोमा से रोजगार मिलना मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादातर नौकरियां देने वाली संस्थाएं प्रोफेशनल स्किल और अनुभव को ही वरीयता दे रही है। ऐसे में सरकार ने नियोजनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है।

इंटर्नशिप

व्यवसायिक डिग्रियां बगैर अनुभव केअधूरी सी लगती हैं। सामान्य विषयों को छोड़ दें तो इंजीनियरिंग, वकालत, चिकित्सा आदि की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप एक बेहतरीन अनुभव तो देता ही है, अपने विषय के व्यावहारिक पहलुओं को जानने, लोगों की आवश्यकताएं समझने में भी मददगार होती है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा इंटर्नशिप मुहैया कराने की घोषणा बेहद स्वागतयोग्य कदम है। बजट में यह कहा गया है कि सरकार देश भर के शहरी स्थानीय निकाय के जरिए प्रशिक्षु इंजिनियर को एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप मुहैया कराएगी। उम्मीद है, इस फैसले से प्रेरित होकर अधिक से अधिक बच्चों को इंटर्नशिप मुहैया कराने की ऐसी ही कोशिशें विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारों के स्तर पर भी शुरू किए जायेंगे।

ऑनलाइन शिक्षा

भारत एक विशाल देश है। देश के कई हिस्सों में आज भी उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मौजूद नहीं हैं। लाखों विद्यार्थी असमय ही पढ़ाई छोड़कर स्वरोजगार अथवा अन्य किसी कार्य में लग जाते हैं। उच्च शिक्षा को या तो वे पूरा नही कर पाते अथवा बीच में ही उन्हें छोड़ना पड़ता है। कईयों को आर्थिक दिक्कतों की वजह से भी आगे की पढ़ाई मजबूरन खत्म करनी पड़ती है। वैसे समय में जब देश के कोने-कोने में ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर

इंटरनेट का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा हो, देश में सस्ते इंटरनेट कनेक्शन मिल रहे हों, सूचना-तकनीकी के इस दौर में करोड़ों लोग स्मार्ट फोन का इस्तेमाल कर रहे हों, ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। सरकार ने उच्च शिक्षा की पहुँच सभी तक हो, इसके लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन कोर्स चलाने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन कक्षाओं के जरिये देश की युवा पीढ़ी ज्यादा लाभान्वित होगी। वे न केवल उच्च शिक्षा पाने के अपने स्वप्न को पूरा करेंगे बल्कि देश के बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी बनने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। सरकार द्वारा डिग्री स्तर तक संपूर्ण शिक्षा ऑनलाइन मुहैया कराना आर्थिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों के अभाव में आगे की पढ़ाई से वंचित लोगों को एक नए अवसर की तरह होगा।

स्टडी इन इंडिया

भारत की वैश्विक पहचान जब मजबूत हो रही हो, भारत को जानने-समझने की उत्सुकता विश्व में बढ़ रही हो, दुनिया भर से बच्चे भारत में पढ़ने आ रहे हों, जरुरी है कि देश में उच्च शिक्षा के लिए विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए ठोस पहल की जाए। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत को उच्चतर शिक्षा का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए भारत सरकार एशिया और अफ्रीका के देशों में'इंड- सैट' आयोजित करेगी। इस परीक्षा के तहत ही विदेशी विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने और छात्रवृति देने हेतु चयनित करने की योजना है।

नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट मसौदे की मानें तो जहाँ भारत से विदेश पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं वैश्विक औसत के हिसाब से देखें तो महज एक फीसदी बच्चे भी भारत नही पढ़ने आते। उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो आज भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की संख्या 50000 से भी कम है। 2014 के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 50 लाख विद्यार्थी अपना देश छोड़ दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए पसंदीदा देशों में भारत का स्थान 26वां है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम पर ध्यान देकर भारत न केवल वैश्विक जगत में उच्च शिक्षा का बेहतर स्थान बन सकता है बल्कि बड़ी संख्या में आने वाले विद्यार्थी दुनिया भर में भारत के दूत बनकर भी जाएंगे।

अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ने का प्रस्ताव

जिस रफ़्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना एक चुनौती बनता जा रहा है। देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सासेवा के लिए योग्य डॉक्टरों की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, वहीं पर्याप्त क्षमता वाले बड़े अस्पतालों को अपने यहाँ आवासीय डीएनबी/एफएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत प्रोत्साहित करने की भी बात कही है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ही स्नातकोत्तर चिकित्सीय अहर्ताएं, डिप्लोमा की मान्यता प्रदान करता है। इस काम को सरकार निजी निवेशकों के साथ आगे बढ़ाएगी।

वैश्विक मांग के अनुरूप तैयार होंगे दक्ष युवा

विदेशों में भारत के शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सीय सहायक कर्मचारियों और देखभाल करने वाले लोगों की बहुत मांग है। केंद्र सरकार ने रोजगार की असीम संभावनाओं और भारतीय प्रोफेशनल की अत्यधिक मांग को देखते हुए स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय व्यावसायिक निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना की घोषणा बजट में की है। इसके जरिये कुशल और सभी मानकों के अनुरूप दक्ष युवा वैश्विक मांग के अनुरूप तैयार हो सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत विविध देशों की भाषाई अपेक्षाओं को भी ख्याल रखने पर जोर दिया जाएगा जिसे विशेष प्रशिक्षण पॅकेज के जरिये हासिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बजट में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी व नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलने की भी घोषणा की गई है। अपराध की घटनाओं की बदलती प्रकृति और आधुनिक समय में देशवासियों की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया यह कदम सराहनीय है और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रुप से बेहतर होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में बजट में की गई घोषणायें महत्वकांक्षी भारत की झलक प्रस्तुत करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन प्रयासों से सबकी पहुँच में अच्छी शिक्षा हो। ■

अभाविप ने आयोजित किया 'रन फॉर नेशन' मैराथन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चंडीगढ़ इकाई द्वारा दो फरवरी को रन फॉर नेशन मैराथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुखना लेकर पर सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शहर के पांच किलोमीटर क्षेत्र का चक्कर लगाया।मैराथन के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक सिराज गहलोत ने बताया कि परिषद द्वारा समय - समय पर विद्यार्थियो के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कडी में दो फरवरी को इस दौड़ का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि मैराथन दो आयु वर्ग में आयोजित की गई थी, जिसमें 15 से 29 व 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की थी। उन्होंने बताया कि विजेताओं को नगद पुरस्कार व स्मृति चिह्व देकर सम्मानित किया गया। सिराज ने बताया कि इस मैराथन के लिए एक हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया । परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम को लेकर संपर्क अभियान चलाया था। मैराथन का शुभारंभ पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, अभाविप के प्रदेश अध्यक्ष राजन भंडारी, चंडीगढ़ महानगर अध्यक्ष डॉ. करण विनायक व महानगर मंत्री अजय सूद ने हरी झंडी दिखाकर किया। मौके पर विनीत जोशी (पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार), कुलदीप तिवारी(अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा उच्च न्यायालय, पुनीत भंडारी, अभाविप पंजाब के संगठन मंत्री राहुल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' फरवरी 2020 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

बेजा विरोध का दि'शाहीन बाग

| अजीत कुमार सिंह |

नागरिकता संशोधन अधिनियम को 11 दिसंबर 2019 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, जो अब कानून का रूप ले चुका है। यह कानून बीते 10 जनवरी को देशभर में लागू हो गया, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक गजट अधिसूचना में दी गई। इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और इसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

सीएए को संसद के दोनों सदनों में चर्चा के उपरांत पारित किया गया। सीएए लागू होने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए मुस्लिम समुदाय को बरगलाना शुरू किया, विरोध प्रदर्शन किये गये। विरोध के दौरान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ में करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

15 दिसंबर 2019 को कुतर्कों और बेजा विरोध की चादर ओढ़े एवं हाथ में संविधान लिए दिल्ली के शाहीन बाग में कथित रूप से संविधान को बचाने के लिए समुदाय विशेष के लोग धरने पर बैठ गये, ये अलग बात है कि इस प्रदर्शन में अधिकांश लोगों को भारत के संविधान और कानून से दूर - दूर तक वास्ता नहीं है। दिशाहीन बाग। जी हां! ठीक पढ़ा है आपने! दिशाहीन बाग ही है। चूंकि जिस भीड़ का कोई उद्देश्य और लक्ष्य न हो, उसे दिशाहीन ही कहेंगे। शाहीनबाग राष्ट्रीय राजधानी का वह इलाका है जो दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद को मुख्य मार्ग से जोड़ता है। इस मार्ग के माध्यम से रोजाना 20 लाख से अधिक आवाजाही करते हैं। दि'शाहीन बाग प्रदर्शन के चलते लोगों को अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे प्रकरण के बारे में अगर आसान शब्दों में कहें तो पत्थर नहीं मारेंगे लेकिन परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। हिंसा खुद करेगें और इसका ठीकरा किसी और पर फोड़ेगे। और ऐसा किया भी, जामिया हिंसा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विरोध के नाम पर पत्थरबाजी, हिंसा और सार्वजनिक वाहनों को फूंकने का मत्था पुलिस पर मढ़ने की कोशिश हुई। भला हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से देश के सतर्क युवाओं ने झूठी खबरों और तस्वीरों का पोल खोल दिया, परिणामस्वरूप देश

भर में उत्पातियों के खिलाफ विरोध के स्वर गूंजने लगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए कथित प्रदर्शनकारियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हाथों में तिरंगा एवं जुबां पर वंदे मातरम का गान करने लगा। यह दीगर बात है कि इसके पहले विद्यालय और सिनेमाघरो में वंदे मातरम का गान करना इस्लामी मान्यता के अनुसार कुफ्र हुआ करता था। जरा सा जाम लगने के बाद मोटे - मोटे हैडलाइन लगाने वाले मीडिया का एक वर्ग भी इस बेजा विरोध को उचित ठहराने में जी – जान से लग गये हैं। जिन प्रदर्शनकियों को लाखों लोगों की परेशानी से मतलब नहीं, उसे मानवतावादी बताने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले इस रास्ते पर दिए जा रहे धरने का 50 से अधिक दिन बीतने को है, लेकिन कथित आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्हें छोटे - छोटे बच्चों का स्कूल छूट जाने, व्यापारियों के दूकान बंद हो जाने, एंबुलेस तक नहीं दिए जाने का जरा सा अफसोस नहीं है। वे इस प्रदर्शन को ऐसा दिखा कर रहे हें जैसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी चेहरा शाहीनबाग है। शाहीन बाग के बहाने पूरे देश में खतरनाक खेल, खेला जा रहा है, जिसको खाद - पानी देने का काम विपक्षी दलों के नेता, कथित बुद्धिजीवि और सेलेक्टिव पत्रकार कर रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि वहां पर बैठने के लिए कथित तौर पर 500 - 500 दीहाड़ी के साथ – साथ जायकेदार बिरयानी भी परोसा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन बाग में पीएफआई के पांच ऑफिस खोले गये हैं।

कट्टरपंथ का नया चेहरा शरजील इमाम

28 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने जिस शरजील इमाम को गिरफ्तार किया है उसे इस्लामिक कट्टरपंथ का नया चेहरा कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। नागरिकता संसोधन कानून की विरोध प्रदर्शन के आड़ में शरजील, पूरे देश में दंगा - फसाद करवाना चाहता था, जिसका उदाहरण 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिये गए जहरीले वायरल भाषण में मिलता है। इस भाषण के वायरल वीडियों वे कहते दिख रहे हैं कि असम व पूर्वोत्तर को भारत से काट दो। रेल की पटरियों पर इतना मवाद डाल दो कि उसे साफ करने में महीनों लग जाये। तीन तलाक, अनुच्छेद 370, राममंदिर के फैसले पर मन महसोस कर बैठने वाले को शरजील के रूप में नया आका मिल गया है। शरजील को बचाने के लिए कुछ लोग तरह – तरह के कुतर्क गढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम के बसंत कुंज स्थित फ्लैट से लेपटॉप और एक सर्जन का डेस्कटॉप बरामद किया है। इसके साथ ही अपराध शाखा ने शरजील के बिहार के जहानाबाद स्थित घर से मोबाइल फोन भी बरामत किया है, जिसके माध्यम दिल्ली पुलिस चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं। शरजील इमाम से पूछताछ में पता चला है कि वह खांटी कट्टरपंथी है। उसके अंदर देश को लेकर काफी नफरत भरा हुआ है। शरजील के मुताबिक भारत को इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए। पूछताछ में शरजील ने यह भी स्वीकार किया कि सभी के सभी वीडियो उसी के हैं जिसमें उन्होंने विवादित भाषण दिये थे। बता दें कि शरजील इमाम दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के शुरूआती दौर में उसके आयोजकों में से एक रहे हैं।

नीरज (लोहरदगा) की मौत पर चुप्पी, जामिया पर बवाल

30 जनवरी को शाहीन बाग से सटे जामियां में अजीबोगरीब घटना घटी, प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने तमंचा लहराते हुए गोली चला दी। गोली किसी शादाब नामक युवक के हाथ में लगा, जिससे वो घायल हो गया। आनन - फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसे अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जामिया की यह घटना देश भर में छाया रहा, कुछ लोगों ने इसे हिन्दूवादी आंतकवाद, तो कुछ ने गोडसे तक कह डाला। ये वही लोग थे जो यह कहते नहीं थकते थे कि आंतक का कोई धर्म नहीं होता। हांलाकि हिंसा कोई भी करे, वह गलत है। उसे किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटी जिस पर सभी के जुबान पर ताला लग गया। घटना झारखंड के लोहरदगा की है, जहां पर 23 जनवरी को नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा मार्च निकाला गया था जिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई । इतना ही नहीं पेट्रोल बम भी फेंके गये। इसके अलावा वाहनों को भी फूंक दिया गया। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गये, जिसमें नीरज प्रजापति भी था। पत्थरबाजी के

दौरान नीरज प्रजापति को गंभीर चोंटे आई, प्रारंभिक इलाज के बाद उसे रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां से दो दिन बाद इलाज हेतु स्थिति गंभीर बताकर उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। नीरज की मौत के बाद सेलेक्टिव चुप्पी छाई हुई है। जामिया की घटना पर हाय - तौबा मचाने वाले को नीरज की मौत पर जरा सा भी तरस नहीं आई, मृतक के परिवार के प्रति संवेदना तक जताने का समय नहीं मिला।

उतर रहा है शाहीन बाग का मुखौटा

देश भर में हिंसा का मुखौटा उतरने के बाद सहानुभूति बटोरने के लिए शाहीन बाग की पटकथा लिखी गई। तिरंगा और वंदे मातरम का गान इसी कवायद का हिस्सा थे लेकिन इनकी तस्वीरें/वीडियों वायरल होने के पहले 'जिन्ना वाली आजादी'के नारे एवं सीएए के प्रदर्शन में 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर लोगों की नजर में आ चुकी थी। सबसे ज्यादा फजीहत इनकी तब हुई जब पैसे लेकर धरने पर बैठने का एक स्टिंग लोगों के सामने आया। लेकिन अगले ही दिन सुनियोजित तरीके इसे जन आंदोलन के रूप में दिखाने के लिए यज्ञ, हवन और अरदास करना शुरू कर दिया। शाहीनबाग के कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मुखौटा धीरे - धीरे उतर रहा है जिसकी बानगी 24 जनवरी को शाहीनबाग के आयोजकों से बातचीत करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया के साथ हुए मॉब लींचिंग की घटना है। दीपक चौरसिया अपनी टीम के साथ वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई और कैमरे को तोड़ा गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। एक तरफ शाहीन बाग के कथित प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि उनकी आवाज को सुनी नहीं जा रही है वहीं उसी कथित प्रदर्शन को कवर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी पहुंचे तो उन्हें कवर करने से रोका गया। देश के इतिहास में शायद ही ऐसा लोकतांत्रिक प्रदर्शन होगा जिसमें शामिल होने वालों को रोका गया हो। ■

अलीगढ़ : अभाविप द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ब्रज प्रांत के अलीगढ़ महानगर में मेधावी छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अभाविप द्वारा इस कार्यक्रम में 1256 छात्र – छात्राओं को सम्मानित किया गया। इंटरस्तरीय प्रतिस्पर्धा में दिव्यांशी सेंगर प्रथम, ललित कुमार द्वितीय एवं पूनम तृतीय रहीं एवं हाई स्कूल स्तर पर गर्वित चन्देल प्रथम, रुक्मणि अग्रवाल, सार्थक सिंह द्वितीय तथा दीक्षा तृतीय रहीं। अभाविप ने इस कार्यक्रम के जरिये जालियांवाला हत्याकांड के बलीदानियों को भी याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद राजवीर दिलेर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण और छात्रों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करता आया है। अभाविप नेप्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से जिन मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया है, बहुत ही सराहनीय है।विशिष्ट अतिथि इं० जगमोहन गुप्ता ने कहा कि युवाओं को अपने करियर के साथ - साथ समाज एवं राष्ट्रहित के लिए भी कार्य करना चाहिए ताकि स्वयं के साथ – साथ राष्ट्र एवं समाज का भी विकास हो एवं देश प्रगतिशील बने।

अभाविप के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ पुष्पेंद्र पचौरी ने कहा कि वर्तमान समय में देश बड़ी चुनौती से गुज़र रहा है और इस चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं को आगे आना होगा। इतिहास गवाह है कि जब – जब देश में कोई चुनौती आई है युवाओं ने बढ़ – चढ़कर उसका सामना किया है। भारत के युवा न केवल अपने करियर के प्रति सजग हैं अपितु राष्ट्रहित के लिए भी तत्पर है। अब समय आ गया है देश के युवा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मौके पर महानगर अध्यक्ष डॉ रविन्द्र राजपूत, महानगर मंत्री मधुर माहेश्वरी, महानगर छात्रा प्रमुख सपना गुप्ता, प्रदेश सह - मंत्री सीटू चौधरी, विभाग संगठन मंत्री योगेंद्र वर्मा, केडी वर्मा आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

ABVP JAMMU KASHMIR ORGANISES MADRASSA STUDENTS CONCLAVE 2020

Regional language must be promoted for taking the education to grass route level : Sunil Ambekar

ABVP Jammu Kashmir held a programme under Vishesh Sampark Abhiyan 2020 in which students from various Madrassas joined the program. The chief speaker of the occasion was Sh. Sunil Ambekar (Former National Organizing Secretary, ABVP), other prominent present were Maulana Naqshbani and Mufti Zakir were the guest of honor and Chief Guest on the occasion.

Sunil Ambekar emphasized on the role of modern education and general syllabus must also be included in the curriculum to be introduced in Madrassa and the nationalist thought which needs to be emphasized in every education institute. He further said that regional language must be promoted for taking the education to the grass route level.

Maulana Naqsbandi said that Sufism in India have always promoted nationalist thought and never made any statement against indian integrity. He submitted memorandum to Sh Sunil Ambekar for promotion and development of separate Madrassa Board for balanced funding and equivalent development of the Madrasaa Students.

Mufti Zakir said that it is indeed an honour to witness such program in which ABVP is promoting students from Madrassa to bring them into main stream at par with other students. He said that madrassa students have been excluded from regular activities by government institute. This is a good platform to development of the feeling of oneness in the country. Madrassa has always tried to develop feeling of National respect.

ABVP State President Dr.A.P Singh provided the information about the role of ABVP in nation building and raising the voice of student. ■

पीएफआई - आतंक का नया प्रारूप

| विनय कुमार सिंह |

पीएफआई आजकल खूब सुर्ख़ियाँ बटोर रहा है, लेकिन गलत वजहों से। ईडी की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पीएफ़आई की ताक़त का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह इस देश का एक मात्र संगठन है जिसकी हैसियत इतने कम समय में इतना धन और जन इकट्ठा करने की है। यही नही, पीएफ़आई का प्रचार तंत्र कितना कारगर है इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी सरकारी मशीनरी को धता बताते हुए वह इस झूठ को देश भर के आम मुसलमानों में फैलाने में सफल रहा है कि सीएए क़ानून इस देश के मुसलमानों के ख़िलाफ है।

पीएफआई की शुरुआत केरल में 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। बाद में कर्नाटक के कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (केएफडी) और तमिलनाडु में मन्नीथा नीति पासाराई (एमएनपी) के साथ इसका विलय हो गया। अन्य राज्यों में भी, जैसे-गोवा के सिटिजन फोरम, राजस्थान की कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसायटी, पश्चिम बंगाल में नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, मणिपुर के लिलोंग सोशल फोरम और आंध्रप्रदेश की एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस के साथ पीएफआई का विलय कर दिया गया। इसके अनुषांगिक संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, इंडियन फ्रैटरनिटी फोरम, कॉन्फेडरेशन ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया, मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क (एमआरएन) और सत्य सारिणी जैसे संगठन शामिल हैं। आज पीएफआई बहुराज्यीय आयाम प्राप्त करने में सफल रहा है। पीएफआई 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एनसीएचआरओ)' और अन्य मानवाधिकार संगठनों के साथ सहयोगी के रूप में भी काम करता है। लेकिन उसकी ये सभी गतिविधियां अपने मुख्य एजेंडे को छिपाने के लिए होती हैं।

पीएफआई का शुरुआती संगठन एनडीएफ मई 2003 में केरल के माराड समुद्र तट पर हुए नरसंहार में शामिल था। इस घटना में इसके काडर ने एक सार्वजनिक नल पर पेयजल को लेकर हुए विवाद में 8 हिन्दू मछुआरों की हत्या कर दी थी। यह घटना बाद में सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गई। 2009 में एक विशेष अदालत ने इसके लिए 65 एनडीएफ कार्यकर्ताओ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 8 जून 2011 को सुधींद्र और विग्नेश नाम के दो लड़कों का मैसूर के महाजन कॉलेज परिसर से अपहरण कर लिया गया और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (केएफडी) के सदस्यों ने इनकी हत्या कर दी। इन लोगों ने अपने संगठन के लिए धन जुटाने के लिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 2006 में केएफडी का पीएफआई में विलय हो गया। गिरफ्तार किए गए केएफडी सदस्यों में आदिल उर्फ आदिल पाशा, अताउल्ला खान, अमीन उर्फ सैयद अमीन, रहमान उर्फ शब्बीर रहमान, कौसर उर्फ मोहम्मद कौसर और सफीर अहमद ऊर्फ सफ़ीर शामिल हैं। । पीएफआई में विलय होने वाली एमएनपी पर नवंबर 1993 में चेन्नई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगा था। इस घटना में 11 आरएसएस कार्यकर्ता मारे गए थे।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया(पीएफआइ) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बड़े से बड़े देश विरोधी कृत्य मानवाधिकार कि आड़ में कर लेता है, और हर राष्ट्र विरोधी कार्य के लिए भी भारतीय संविधान की दुहाई ही देता है। वैसे पीएफआई का मानना है कि हमास, तालिबान, और अलकायदा के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी हैं। आतंकवाद पर इसके विचार मानवाधिकार संगठनों जैसे नहीं हैं। अपने एक प्रकाशन में वह कहता है: "हम फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और इराक में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एकजुटता की घोषणा करते हैं।" यह भारत को मुसलमानों के दुश्मन देशों के मित्र के रूप में भी देखता है। कोझिकोड में 2009 में अपने पहले राजनीतिक सम्मेलन में, पीएफआई अपने प्रभावशाली कोझिकड घोषणापत्र के साथ सामने आया था। इसमें, पीएफआई ने ये घोषणा की कि "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक अमेरिकी एजेंडा है, यह एक राजनीतिक चाल है जिसे विश्व वर्चस्व की सोच वाली आधिपत्यवादी शक्तियों ने आकार दिया है।

प्रत्यक्ष रूप से पीएफआई के अनुयायिओं की संख्या बहुत बड़ी है, यहां तक कि केरल, बिहार,झारखंड,दिल्ली और उत्तरप्रदेश से बाहर के राज्यों में भी। पीएफआई का वर्तमान में 12 राज्यों में व्यापक संगठन और 23 से ज्यादा

राज्यों में सक्रियता है। राजनीतिक तौर पर पीएफआई खाने के अधिकार, बोलने के अधिकार, काले कानून जैसे मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाती है पर रणनीतिक मोर्चे पर संगठन इस तरह के प्रयासों में व्यस्त है, जिसका लक्ष्य "100 वर्षों का मुस्लिम एजेंडा - रोड मैप 2047" का व्यापक प्रसार करना है। इसमें 2047 तक व्यापक उपायों से 'मुस्लिम सशक्तिकरण' पर विचार रखे गये हैं, ताकि वे अपनी श्रेष्ठता फिर से हासिल कर सकें , जिसे वे स्वतंत्रता से पहले भोग रहे थे, खास कर मुग़ल काल में . इस उद्देश्य के लिए संगठन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार, कक्षाओं आदि का आयोजन करता रहा है ।

पीएफआई के साहित्य में बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद के दंगों और गुजरात "नरसंहार" को इस तरह क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है, जिससे ये परिलक्षित हो कि किस तरह भारत सरकार मुस्लिमों पर जुल्म करती रही है। पीएफआई का दावा है कि भारतीय मसुलमान गोमांस खाने के नाम पर हिन्दुओं द्वारा पीड़ित किए जाते हैं । मीडिया लगातार उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है और आतंकी गतिविधियों में मुसलमानों की भूमिका को बिना जाँच के ही स्वीकार कर लेता है । मुस्लिम समुदाय के भीतर व्यापक समर्थन प्राप्त करने में पीएफआई की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण इसकी संगठनात्मक क्षमता थी। इसकी 'फ्रीडम परेड' इसकी कैडर क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन है। पिछले दो सालों में 15 अगस्त को, पीएफआई कैडर ने अर्धसैनिक संगठनों के समान वर्दी पहन कर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के शहरों में श्रेष्ठ ढंग से एकीकृत मार्च का प्रदर्शन किया । केरल के पूर्व डीजीपी विन्सन एम. पॉल के अनुसारः "पीएफआई में शामिल होने वाले सभी मुस्लिम युवाओं को मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और पैसा दिया जाता है। संगठन खाड़ी देशों में नौकरी के संबंध में भी सहायता करता है।"

यह भी उल्लेखनीय है कि एसडीपीआई और राष्ट्रीय इमाम काउंसिल ने क्रमशः 13 से 15 राज्यों में अपनी संगठनात्मक इकाइयां स्थापित कर ली हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन्स इन इंडिया (सीएफआई) 11 से अधिक राज्यों में सक्रिय है, जबकि एनसीएचआरओ 6 से अधिक राज्यों में सक्रिय है। इस बीच इंडियन फैटरनिटी फोरम (आईएफएफ) की इकाइयां सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में मौजूद हैं। संगठन के केरल प्रमुख नसरुद्दीन एलामारम के अनुसारः "पीएफआई का विस्तार हो रहा है क्योंकि मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों में ऐसी भावना घर कर गई है कि उन्हें धोखा दिया गया है।" पंजाब में पीएफआई का उद्देश्य खालिस्तान की मांग और इसके आंदोलन को फिर से शुरू करना है। पीएफआई वर्ष 2014 में पंजाब के कई हिस्सों में दलित समूहों द्वारा आंदोलन और कुछ दंगों के साथ भी जुड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल में दलित आंदोलन में स्वघोषित दलित समूहों और इस्लामिक कट्टरपंथिओं के बीच अपवित्र गठबंधन स्थापित हो चुका है। झारखंड में इनका सम्बंध माओवादीयों से स्पष्ट हो चुका है, यही नहीं प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साज़िश रचने वाले गिरफ़्तार अर्बन नक्सल रोना विल्सन का सम्बंध भी झारखंड पीएफआइ से बहुत ही गहरा रहा है। इस मामले की छानबीन करने वाली पुणे पुलिस को झारखंड के ऐसे दर्जनों मोबाइल नंबरों का पता चला है जिनका उपयोग प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साज़िश रचने वाले गिरोह के द्वारा किया गया था।

केरल पुलिस का आंतरिक सुरक्षा जांच दल (आईएसआईटी) भी पीएफआई की गतिविधियों की जांच कर रहा है। आईएसआईटी ने दावा किया है कि उसने पूरे केरल में डाले गए छापों के दौरान तालिबानी सामग्री, वीडियो और "अत्यधिक सांप्रदायिक" और विध्वंसक साहित्य जब्त किए हैं। केरल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक शपथपत्र में केरल सरकार के उप सचिव (गृह), राजशेखरन नायर ने दावा किया था कि आईएसआईटी ने अलकायदा से जुड़ी सीडी पाई है। अदालत को पीएफआई के लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से कथित संबंधों के बारे में भी बताया गया।

महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने भी पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव मिर्जा हिमायत बेग और शेख लाल बाबा मोहम्मद हुसैन फरीद उर्फ बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के आतंकी संबंधों का खुलासा किया है। महाराष्ट्र एटीएस के अनुसार, बेग एक सक्रिय पीएफआई कार्यकर्ता था और वह लश्कर-ए-तैयबा के लिए रंगरूटों की खोज करने में शामिल था।

पीएफआई मूल रूप से एक संगठन न होकर सैकड़ों संगठनों का एक समूह है जिससे कई और कट्टरपंथी संगठन जुड़ते ही जा रहे हैं और उन्होंने अपने को एक संगठन के रूप में न बढाकर अपना विस्तार एक विचार के रूप में किया है। एक ऐसा विचार जो संगठन के प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अपनी सक्रियता बनाये रख सके। ■

(लेखक पीएफआई पर रिसर्च कर रहे हैं एवं ये उनके निजी विचार हैं।)

Dissection of Pak's frustration

| K.N. Pandita |

Imran messaged his debut as Pak PM with India-Pak peace rhetoric. Pak army imagined that with a former popular cricketer as the show boy, it can repair its terror-daubed image and pass for a peace-loving country purporting to blunt India's thrust. New Delhi stood fast by its known stand that talks and terror do not go together. This ended up in Imran's first frustration as the PM.

Moral bankruptcy made the Pakistan army hide for her people the Balakot pincer strike. However, the new threat perception that has begun to haunt her is the vulnerability of her border with India. Balakot forced the Pak army to recast its border defense strategy. She has moved nearly 200,000 troops and military machine along the PoK border with the Union Territory of Jammu Kashmir. The alarm of Indian forces launching a blitzkrieg on Muzaffarabad is slowly but fatally eating into the vitals of the Pak army. This is its second frustration.

JK Reorganization Act 2019 came as a stunning shock more to Pakistanis and their army than to the Kashmiri separatists and their sympathizers among Indian pseudo-secularists. Pakistan shedding crocodile's tears for Kashmiris for seven decades and more found to its utter surprise that it had to shed real tears for itself and not for Kashmiris. The Act 2019 worked a bombshell on Pak military echelons because it was the simmering pot of Kashmir issue that greased Pak army's fund amassing machine. It will be noted that with the passing of the new Act and reorganization of former J&K State, Pakistan's Kashmir narrative began to undergo a deep change. Fight for Kashmiris changed into a fight for Islam, to be precise, for Sunni Wahhabi Salafi Islam.

Imran's first reaction was to downgrade the diplomatic mission of India. Then it went knocking at the door of the Security Council, which, however, proved imbecile. Imran rushed to Washington to open the plethora of complaints in front of President Trump. Responding to media queries, the President said that Imran was a former cricket player and a handsome man. He trivialized the meeting with a hearty laugh. No European power showed any interest in Pak's tantrum against India's constitutional amendment.

After facing the third frustration, Imran Khan hesitatingly knocked at the door of the OIC. No satisfactory response was available from the Arab world. Saudis said they closely follow the developments in the region and insisted that the issue could be resolved based on international resolutions. Shimla Resolution of 1972 and 2003 Ceasefire Resolution between the parties is among the plethora of resolutions on Kashmir and Pakistan has trampled these under the iron heel. Dubai said a constitutional amendment is nothing extraordinary in a democratic setup and UAE bluntly said it was an internal affair of India.

After getting bruised and mauled by a cold and dispiriting response from the Arab world, Imran found some hope with Turkey's President Endogen and Malaysian Premier Dr. Mahathir.

Finally, these frustrations pushed Imran to the most dangerous and self-destructing course of talking about the weapon of mass destruction. Imran Khan and some irresponsible members of his Council of Ministers have been issuing threats of being under pressure to think of the use of nuclear alternative. To justify the use of the dirty bomb, Pakistan has been floating absurd rumors she thinks would bring legitimacy to making the first nuclear strike. For example, Pakistan claims that India has broken the wire fencing at least at half a dozen places along the LoC, and deployed nuclear powered Brahmos missiles... Imran has been sending letters to the US and other European governments raising the bogey of an imminent attack by India to wrest the part of J&K illegally under her occupation. This is now a frustration that Pakistan finds difficult to control.

Pakistan declined to participate in the Kuala Lampur Islamic meet because Saudi Arabia summoned Imran to Riyadh and warned him that Pakistan's participation in Kuala Lampur Islamic

Summit would be considered by the Saudis as an act inimical to the interests of the Saudis and the OIC. Saudis further warned him to desist from creating a wedge between Semitic and non-Semitic Islamic countries as was the plan of anti-Saudi Islamic countries like Turkey, Iran, and Malaysia. The move was jointly initiated by Malaysia, Turkey, Iran, and Pakistan with Malaysia Prime Minister Dr. Mahathir as the prime mover having become an Islamist at 94.

The recent visit of the foreign minister of the Saudi Kingdom to Islamabad was interpreted by Pakistani media as Riyadh's indication to call a meeting of the OIC on Kashmir. Imran Khan knows that OIC is a toothless entity, and the media hype is only to silence the critics at home and put an ointment on his frustration. OIC is a spent force because the Islamic world is divided. Moreover, India has very cordial relations with the Saudi Kingdom to the extent that Saudi Arabia honored PM Modi with that country's highest civilian award. Saudis are incepting Asia's largest oil refinery in Mumbai and the two countries trade runs into billions of dollars. Likewise UAE and Dubai, too, have close relations with India and enormous commercial interests among them. Two-thirds of India's oil imports are from Saudi Arabia and millions of Indians are working in the Gulf countries. All this contributes to the frustration of Pakistan. The question is this: Who is at the root of all these frustrations? This is the real question. The huge brigades of jihadi terrorist organizations created by the Pakistan army and funded by the state exchequer are the cause of disaster awaiting Pakistan.

Pakistan has intensified shelling and firing along the border. The entire LoC is ringing with gunfire. Pakistan is desperate that India should react in anger and begin a war so that by playing an oppressed party, she can win the sympathy of the international community. India, on principle, never initiates war anywhere. She will thus disappoint Pakistan.

J&K is integrated into the Indian Union. What is under the illegal occupation of Pakistan and China is part of the territory of the Indian Union. The Indian Union has the right and sanction of international law to retake its illegally snatched territory. Therefore, the task before the Union of India after the abrogation of Art... 370, etc. is to first recapture Muzaffarabad and thus seal off the Krishnaganga Valley. Then India will bring about a link up with the Wakhan corridor where there is 116 km long border between Wakhan Arm and Gilgit territory. This provides India a route to Afghanistan and Central Asia. India has to establish the link because Pakistan's refusal to India's over flights westward necessitates the retaliatory action. There is already large scale discontent simmering among the people in Krishnaganga Valley and GilgitBaltistan region against the tyrannical rule of Pakistan. India will come to the rescue of her people as they are originally the nationals of the Indian Union.

Therefore, before counting her Kashmir woes to the Islamic countries, Imran's emissaries made several jaunts to Beijing expecting China to rattle the sword. However, China did not go beyond her concerns for the Sino-Indian border in Ladakh, thereby underestimating the intensity of Pakistan's. None of the Arab Islamic countries –Iran included—showed any concern on Kashmir development.

India took the bold and unexpected decision of putting an end to J&K's special status. Transformation of the State into two Union Territories on 5 August 2019 by the Indian Parliament created an embarrassing situation for Pakistan. The Kashmir which Pakistani terrorist legions had vowed to take away from India got integrated into the Indian Union territorially as well. Pakistan spat filth that meant nothing. It tried to instigate the Indian opposition particularly the Congress, Left, pseudo-secularists and the Indian Muslim. Now with the inclusion of Naxals, they have formed a new front named Peoples Front of India, PFI.

Frustrated Imran made a half-hearted appeal to the Islamic countries without talking about the name of OIC. Saudis said they were watching the situation in JK and advising restraint expected the issue to be resolved in the light of international resolutions. Shimla Agreement of 1972 and the Ceasefire Agreement of 2003 are part of the international/bilateral resolution both of which have been trampled underfoot by Pakistan. Dubai said constitutional amendments are nothing new in a democratic country and the UAE bluntly said that there was no comment on India's internal affairs. Of course apart from China (which however confined its remark to Ladakh only) Turkey and Malaysia. ■

दत्तोपंथ ठेंगड़ी जी की जन्मशती पर विशेष आलेख श्रृंखला - 1

पीढियां प्रेरणा प्राप्त करेंगी पूज्य दत्तोपंथ ठेंगड़ी जी से

ठेंगड़ी जी जहां कहीं होते युवक उन्हें घेरे खड़े रहते थे। चाहे वह शाखा का एकत्रीकरण हो, संघ के विभिन्न शिविर या वर्ग हो, भारतीय मजदूर संघ का या किसी अन्य संस्था का कार्यक्रम हो लोग उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। जहां वे होते वहीं एक मजमा सा बन जाता। पहले संघ में एक बात कही जाती थी कि संघ के कार्यकर्ता को अड्डेबाज होना चाहिए अर्थात् लोगों का जुटान, माहौल हंसी खुशी वाला और अपने लक्ष्य और व्यवहार के प्रति सतत जाग्रत।

। सुशील कुमार ।

14 अक्टूबर 2004 तक वे हमारे साथ थे। उन्हें गए अभी 16 वर्ष भी नहीं हुए। देश-विदेश में हजारों लोग, शायद यह संख्या लाखों में है, जिन्होंने उनको देखा, सुना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके साहचर्य का सुख सहेजा, उनका सरल व्यवहार देखा, उनके साथ देश और विश्व की स्थिति-परिस्थिति, विभिन्न विचार प्रवाह, उन विचारों की दुर्बलता और बल को गहराई से जानने, समझने और परखने का प्रयास किया।

जिन दर्जनों संस्थाओं के जन्म, पल्लवन और पुष्पित होने के वे कारणीभूत थे- उनमें काम किया। उनको छोटे से बीज से विशालकाय वटवृक्ष होते देखा, बल्कि उसमें सहयोग किया- वे सभी तो अभी मौजूद हैं। सोचता हूं 40-50 वर्ष के बाद जब उनके बारे में लोगों को पता चलेगा तो सहसा यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरा पर आया होगा। वे एक दिव्य पुरुष थे। उनका जीवन मानों एक पौराणिक आख्यान हो। साधारणतः इतना अधिक काम करना एक लौकिक प्राणी के लिए सम्भव नहीं- डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई प्रखर विचारकों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में दस जीवन जितना काम किया।

'दत्तोपंत ठेंगड़ी : जीवन दर्शन' नामक ग्रंथमाला 9 खंडों में प्रकाशित हुई है। सुप्रसिद्ध सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथों के संपादक श्री अमरनाथ डोगरा कहते है कि सम्पूर्ण ठेंगड़ी जी को शब्दों में सहेजना सम्भव नहीं- यह तो केवल झलक मात्र है। अभी कोई पुरुषार्थी इस पर काम करे, इसे विस्तार दे, इसे ठीक से सहेजे, संवारे, इसका संपोषण और संवर्धन करे, इसकी बहुत संभावना और आवश्यकता है। देखें कब कौन इसको आगे बढ़ाता है।

अन्तरताने के इस युग में WhatsAppपर अभी इसी सप्ताह मुझे एक संदेश- उपदेश मिला

सरल रहें : ताकि सब आपसे मिल सके।
तरल रहें : ताकि आप सबमें घुल सकें।।

मैं इन शब्दों की गहराई में उतरा। मुझे लगा बात तो एकदम ठीक है, पर इसे साधना अति दुष्कर। फिर माननीय ठेंगड़ी के जीवन पर ध्यान गया तो लगा वे सचमुच ऐसे ही सरल और तरल थे। वे इतने सरल थे, बहुत बड़े होने पर भी सहज उपलब्ध थे, उनके व्यवहार बातचीत में से कहीं भी यह नहीं लगता था कि वह इतने बड़े हैं। वे सभी के लिए सदा सहजता से सुलभ थे। उनका टैक्सी ड्राइवर, उनके बाल बनाने वाला, उनके आवास की सफाई करने वाला, उनके लिए रसोई तैयार करने वाला- सभी तो उनसे सहज थे- सभी उनसे खूब

बातें करते थे, खूब चर्चा करते थे, उन्हें अपने परिवार का बड़ा मानकर उनसे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक सभी समस्याओं का समाधान साधते थे। ये तो सब रहे उनके लिए कुछ काम करने वाले- पर हम जैसे हजारों कार्यकर्ता जो उनके लिए किसी उपयोग के नहीं थे- वे भी उनसे मिलने में कभी संकोच नहीं करते थे। वे हमारी सामान्य चाय आदि से लेकर सभी प्रकार की चिंता करते थे। हम तो ठहरे उनके अनुयायी जैसे, उनके विचारों के ही अनुगामी- पर उनके विचारों के विरोधियों की भी एक बड़ी संख्या है जो उनसे मिलना चाहते थे, उनके साथ समय बिताना चाहते थे। उनके घोर वैचारिक विरोधी भी उनके साथ रहना चाहते थे। मजदूरों के बीच काम करने वाले अनेक कामरेड भी उनकी सरलता व शिष्टता के मुरीद थे।

इस कारण से कई बार बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक और हरियाणा में भारतीय मजदूर संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रोफेसर सुखनन्दन सिंह जी ने एक ऐसी ही विचित्र स्थिति का वर्णन किया। बंगाल के एक कामरेड, शायद कोई बनर्जी दादा थे, वे दिल्ली आए और मान्यवर ठेंगड़ी जी के अतिथि बने। उनका निवास झंडेवाला में किसी कमरे में निश्चित हुआ। सरदार सुखनन्दन सिंह जी को उनकी देखरेख में उसी कमरे में रहने के लिए कहा गया। दादा चेन स्मोकर थे- एक के बाद एक सिगरेट फूंकते थे। सुखनन्दन सिंह जी ठहरे पक्के सिक्ख। यह ठेंगड़ी जी के कारण ही सम्भव हुआ कि सरदार जी यह सब झेल गए। उन्होंने बताया कि सवेरे सारे कमरे में से बीन-2 कर सिगरेट टोटे इकट्ठा कर उन्हें इस प्रकार से फेंका कि किसी के ध्यान में नहीं आवे।

वे तरल भी थे। सभी के साथ घुल जाना उनका स्वभाव था। उन्होंने अनेक संस्थाओं का नेतृत्व किया। आन्दोलनों को, प्रदर्शनों, गेट मीटिंग्स और छोटी बड़ी सभाओं को भी सम्बोधित किया, पर जिसे नेतागिरी कहते हैं, वह उनके स्वभाव में बिल्कुल नहीं थी। भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशनों में सामान्य श्रमिक जैसा रहना, बात करना, व्यवहार करना पसंद करते थे। भोजन या चाय के समय भी उन्हीं के बीच बैठकर या खड़े होकर सब ग्रहण करते थे। कोई नहीं पहचानने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ सकता था कि यही व्यक्ति सभी को चालना देने वाला है। उनका कहना रहता था कि कार्यकर्ता का कैमरे के पीछे रहकर काम करना ठीक है, वही अधिक काम भी कर सकता है। अपने इस स्वभाव के बीच भी वे कई बार एक मजेदार बात भी करते थे। सभी कार्यकर्ताओं को अपने लक्ष्य के प्रति सदा जाग्रत रहना चाहिए। मजदूर क्षेत्र कुछ ऐसा है कि कभी-कभी अपने पास से पैसे देकर अपने लिए माला की व्यवस्था कर उसे किसी के द्वारा पहनवाने का ड्रामा तक करना पड़ता है।

जहां कहीं वे होते युवक उन्हें घेरे खड़े रहते थे। चाहे वह शाखा का एकत्रीकरण हो, संघ के विभिन्न शिविर या वर्ग हो, भारतीय मजदूर संघ का या किसी अन्य संस्था का कार्यक्रम हो लोग उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहते थे। जहां वे होते वहीं एक मजमा सा बन जाता। पहले संघ में एक बात कही जाती थी कि संघ के कार्यकर्ता को अड्डेबाज होना चाहिए अर्थात् लोगों का जुटान, माहौल हंसी खुशी वाला और अपने लक्ष्य और व्यवहार के प्रति सतत जाग्रत।

10 नवम्बर 1920 को उनका जन्म हुआ- अभी उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रारंभिक काल में वे उससे जुड़े रहे। छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे, अतः परिषद की पत्रिका छात्रशक्ति ने भी उनसे संबन्धित सामग्री को पत्रिका में संजोने का विचार किया है। आपको आगामी अंकों में यह सामाग्री मिले- ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ■

(लेखक रा. स्व. संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं।)

पूर्वोत्तर में शांति का मार्ग प्रशस्त : बोडो समझौता

| श्रीहरि बोरिकर |

भारत विविधताओं का नाम है। अनेकों मत, भाषा, मान्यताएं एवं भावनाएं समेटे यह भूखंड सदियों से दुनिया को अनेकता में एकता की राह दिखाते आया है और यही तो इस देश की सुंदरता है! भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र इसी का एक जीवंत उदाहरण है। भारत का यह क्षेत्र न सिर्फ अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अनेकों वर्षों से सैकड़ों अलग - अलग जनजातियां अपने - अपने धरोहर को संजोते हुए अधिकांश शांति के साथ रहते आये हैं। इन्ही जनजातियों में से एक है असम की बोडो जनजाति।

बोडो जनजाति असम में सबसे बड़ा वनवासी समूह है। बोडो असम की जनसंख्या का 5-6 फीसदी हैं। बोडो समूह एक वृहद बोडो-कछारी परिवार का हिस्सा है जिनका शासन एक समय ब्रह्मपुत्र के उत्तर से होते हुए नागालैंड के दीमापुर तक फैला हुआ था। कछारी राजाओं की राजधानी भी तब दीमापुर ही हुआ करती थी। कहा जाता है कि तिब्बती-ब्रह्मदेश की भाषा बोलने वाली यह जनजाति ने असम में सैकड़ों वर्षों पहले आके बसना प्रारम्भ किया था और इसी आधार पर इन्हें असम के सबसे पुराने बाशिंदों में गिना जाता है। मान्यताओं के अनुसार बोडो जनजाति के तार महाभारत के कई घटनाओं से भी जुड़ते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कछारी राजा ने भी अन्य राजाओं के साथ भाग लिया था। महाभारत के अनुसार पांडवों में से एक महाबली भीम की शादी जिन हिडिम्बा नामक युवती से हुई थी, वह इसी बोडो जनजाति की ही सदस्य थीं।

वर्तमान में 'बाथौ' सम्प्रदाय (हिन्दू धर्म का ही एक अंग) को मानने वाले बोडो समूह 'शिजू' नामक पौधे (रेगिस्तान में उगने वाले नागकनी या कैक्टस की एक प्रजाति) को भगवान शिव का ही रूप मानकर पूजा करते आये हैं। अपनी बोडो भाषा को लेकर शुरू से ही भावुक व सचेत इस समुदाय ने पूर्वोत्तर में अन्य जातियों के बसने के साथ अपनी भाषा के संरक्षण हेतु आवाज़ उठाने शुरू किए। इसी क्रम में सबसे पहले वर्ष 1966-67 में प्लेन ट्राइबल्स कॉउन्सिल ऑफ असम के समक्ष 'बोडोलैंड' की मांग उठाई गई थी। अवैध प्रवासियों को मुद्दा बनाकर 1979 में असम आंदोलन शुरू हुआ। 1985 तक चले इस आंदोलन का अंत तब हुआ, जब राजीव गांधी ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) और असम सरकार को साथ बिठाकर एक असम अकॉर्ड पर दस्तखत कराए। असम आंदोलन के तहत असमिया संस्कृति और पहचान को सहेजने का वादा किया गया। बोडो गुटों की मांग भी संस्कृति और पहचान की रक्षा की ही थी। असम अकॉर्ड को बोडो गुटों ने दो तरह से लिया- बोडो अपनी पहचान के प्रति और सचेत हो गए, क्योंकि अकॉर्ड असमिया पहचान की बात करता था। बोडो गुटों को अपनी मांगों को उठाने और मनवाने का जो तरीका अपनाया वह था आंदोलन और विद्रोह। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने इस मांग को नए सिरे से उठाया. तब ABSU के नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ने नारा दिया था- Divide Assam 50-50 (यानी असम को आधे आधे हिस्से में बांटो)। अलग बोडोलैंड की मांग के लिए राजनीतिक संगठनों के साथ उग्रवादी संगठन भी बने। अक्टूबर, 1986 में रंजन दैमारी ने बोडो सिक्योरिटी फोर्स (BDSF) नाम से एक उग्रवादी संगठन बनाया। BDSF ने ही आगे चलकर अपना नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) किया। NDFB का नाम सुरक्षाबलों और आम लोगों पर हमलों, हत्याओं और फिरौती के कई मामलों में आया। अक्टूबर, 2008 में असम में NDFB के किए बम धमाकों में 90 लोगों की जान गई। इन्हीं धमाकों में जनवरी, 2019 में NDFB के 10 सदस्यों और रंजन दैमारी को दोषी पाया गया था। इन धमाकों के बाद NDFB दो गुटों में बंट गया

था। एक गुट गोबिंदा बासुमातारी का, जिसे NDFB-P कहा गया। दूसरा गुट दैमारी का। NDFB के धड़े बंटते रहे, लेकिन हिंसा का क्रम बना रहा। 2012 में बोडो-मुस्लिम दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई और 5 लाख लोग बेघर हुए। दिसंबर, 2014 में बोडो अलगाववादी गुटों ने असम के कोकराझार और सोनितपुर में 30 से ज़्यादा लोगों को मार डाला।

इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों ने कई तरह के प्रयत्न किये, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पहला 1993 में हुआ था। तब बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बनाए गए थे, लेकिन संघर्ष जारी रहा। दूसरा 2003 में केंद्र, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स द्वारा हस्ताक्षरित वह संधि थी जिसमें असम के भीतर ही बोडो बाहुल्य क्षेत्रों को स्वायत्तता देकर एक अलग बोडोलैंड टेरिटोटियल कौंसिल, BTC का गठन किया गया। इस कौंसिल में बोडो बहुल 3082 गांवों को सम्मिलित किया गया तथा इस क्षेत्र को कई रियायतें व सरकारी सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई, जिससे बोडो अपनी संस्कृति व पहचान को सुरक्षित रख सकें। वर्तमान में असम में चार ज़िले बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD के तहत आते हैं- कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी, चिरांग। यहां कई बोडो जनजातियां बसती हैं। 24 नवंबर, 2019 को भारत सरकार ने NDFB पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। इसके बाद इसी वर्ष 11 जनवरी को आखिरी बोडो उग्रवादी गुट NDFB-S ने सरकार के सामने समर्पण की घोषणा कर दी। गुट के करीब 50 लड़ाकों ने म्यांमार का अपना बेस छोड़ा और चीफ बी साओराइग्वारा के साथ भारत-म्यांमार सीमा के पास आत्मसमर्पण कर दिया।

इसी क्रम में बीते 27 जनवरी को तीसरा व आखिरी बोडो शांति समझौता दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ। समझौते के वक्त गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, NDFB के चारों गुट और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के लोग मौजूद थे। केंद्र और असम में गृह मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित थे। इस समझौते के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि NDFB अलग बोडोलैंड की मांग को छोड़कर व उसके लगभग 1550 लड़ाके हथियार डालकर अब मुख्यधारा में प्रवेश करेंगे। सरकार भी इन उग्रवादियों के पुनर्वासन के लिए कई सारे प्रयत्न व धनराशि आवंटित करने को तत्पर है, जिसमें से 1500 करोड़ की राशि तत्काल प्रभाव से जारी भी कर दी गयी जो इन क्षेत्रों के विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।

एक छात्र संगठन के नाते विद्यार्थी परिषद ने भी निरंतर प्रदेश में शांति स्थापित रहे, इसके लिए अथक प्रयास जारी रखे। ABSU के साथ हर तरह के संवाद स्थापित करने के साथ बोडो छात्रों के समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने व संघर्ष करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव आगे खड़ी रही। 2016 में ABVP द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई 'पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद' में पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातियों से जुड़े छात्र नेताओं के साथ साथ ABSU की उपस्थिति इन शांति प्रयासों की द्योतक बनी जिसमें सभी छात्र नेताओं से एक सुर में हिंसा के सभी स्वरूपों के परित्याग व साथ मिल जुलकर क्षेत्र के विकास व छात्रों के जरूरतों के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। इन सभी छोटे - छोटे कदमों से प्रदेश व क्षेत्र में जो वातावरण उत्पन्न हुआ आज वही इन बड़े बदलावों के रूप में हम सभी के समक्ष परिलक्षित हो रहा है। देश मे शांति स्थापित करने में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई या अपना जीवन खपाया आज उन सबके प्रयासों को भी सच्चे हृदय से स्मरण करने का अवसर है। ■

(लेखक अभाविप के अखिल भारतीय राज्य विश्व विद्यालय कार्य प्रमुख हैं, आप लंबे समय तक पूर्वोत्तर के संगठन मंत्री भी रहे हैं।)

लखनऊ : राष्ट्रीय कला मंच द्वारा युवा उत्सव का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रकल्प राष्ट्रीय कला मंच, अवध प्रांत द्वारा लखनऊ में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही नित नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में अपनी पहुंच को लगातार बढ़ा रही है। युवा को गतिशील कहा जाता है तो हमें अपनी यह गति सही दिशा में लगानी होगी, तभी देश के जिस पुनर्निर्माण की बात विद्यार्थी परिषद् द्वारा की जाती है, वह संभव हो पाएगा। अभाविप लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित युवोत्सव कार्यक्रम इसी कड़ी में विद्यार्थियों तक पहुंचने की एक सफल पहल है। जिस प्रकार से पिछले 12 जनवरी से लेकर आज समापन कार्यक्रम तक पूरे लखनऊ महानगर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को मंच देने का काम राष्ट्रीय कला मंच द्वारा किया गया है यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। ओपन माइक, जैम, काव्यांजलि, फेस पेंटिंग एवं मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अभाविप ने कॉन्वेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक तरह के विद्यार्थियों तक पहुंचने में सफल हो रहे हैं।

वहीं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीनीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज देश में जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं,उसे देखकर देश विरोधी ताकतें परेशान हैं। यही कारण है कि देश के शैक्षिक परिसरों को निशाना बनाकर,ऐसा माहौल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि यहां सब परेशान है, लेकिन देश की जनता इन सब वाकयों के पीछे की राजनीति को जान रहे हैं।

राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित युवोत्सव 2020 का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय के जे. के. सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ काव्यांजलि के साथ हुआ जिसमें तमाम युवाओं द्वारा ओजस्वी कविता पाठ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी, अभाविप के प्रान्त अध्यक्ष डॉ सर्वेश सिंह, प्रान्त मंत्री अंकित शुक्ला जी, राष्ट्रीय मंत्री राहुल वाल्मीकि, लखनऊ विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ उदय प्रताप सिंह का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रुप से अभाविप के पूर्व प्रांत अध्यक्ष राकेश द्विवेदी, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ अमित कुशवाहा, राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत प्रमुख प्रो. गोविंद पांडे,राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत संयोजक आशुतोष श्रीवास्तव, प्रांत संगठन मंत्री घनश्याम शाही,महानगर मंत्री अभिमन्यु प्रताप, विभाग संगठन मंत्री अंशुल, महानगर संगठन मंत्री अनुज आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गरिमा उत्प्रेती, शिवेंद्र प्रताप सिंह एवं कामायनी वाजपेई ने संयुक्त रूप से किया। ■

निर्भया कांड के दोषियों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर फांसी टालने की घटना क्या त्वरित संवैधानिक सुधारों की मांग करती है?

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों की फांसी का इंतजार पीड़ित परिवार समेत पूरा देश लंबे समय से कर रहा है, लेकिन दोषियों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर बार – बार फांसी को टालने की कोशिश की जा रही है। निर्भया की मां ने यहां तक कह दिया कि मेरी बेटी के हत्यारों, दरिंदों के लिए विकल्प है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। इस घटना के बाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किन प्रावधानों के चलते निर्भया के दरिंदे अपनी फांसी की सजा में अड़ंगा डालने में सफल हो रहे हैं । इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष एक खाका पेश किया। उन्होंने दोषियों द्वारा कानूनी उपचार की आड़ में कानून से किए जा रहे खिलवाड़ की तस्वीर पेश की। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय छात्रशक्ति के संवाददाता उत्कर्ष श्रीवास्तव ने "निर्भया कांड के दोषियों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर फांसी टालने की घटना, क्या त्वरित संवैधानिक सुधारों की मांग करती है" विषय पर देश भर के लोगों से बात की और उनके विचार जाने। प्रस्तुत हैं चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –

हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपराधियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मगर दोषियों के पास पहले राष्ट्रपति के पास जाने का विकल्प और राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती देने का विकल्प मौजूद था । कुछ अपराधियों ने इस विकल्प का इस्तेमाल कर लिया, जबकि कुछ का अभी शेष है. यह पूरी प्रक्रिया कानून सम्मत है और ठीक भी। इस प्रक्रिया पर मीडिया समूह तथा राजनीतिक दल अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह इंगित करता है कि हमने न्याय की पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझा नहीं है या हम प्रक्रियागत न्याय में विश्वास नहीं करते हैं. हमें इस बार पर संदेह नहीं होना चाहिए कि इस देश की अदालतें किसी भी दोषी, भले ही उसे मौत की सजा क्यों न हुई हो, के साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करतीं । और ये हमारे न्याय पद्धति और संविधान की विशेषता भी है ।

- **अंकित तिवारी,** एल०एल०बी०-द्वितीय वर्ष, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

निर्भया मामले में दोषी फांसी से बचने के लिए रोज नए-नए दांव चल रहे हैं। अब एक दोषी मुकेश सिंह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देते हुए इसकी न्यायिक समीक्षा की मांग की है। इसके पहले दोषियों की फांसी पर पटियाला कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोषी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और फांसी की तारीख नजदीक आने से पहले कोई न कोई याचिका दायर करके सजा टलवाते जा रहे हैं। ऐसे तो इस प्रकार के केसों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा।

- **राम प्रकाश शुक्ल,** पूर्वी एशियन विभाग, जापानी भाषा-द्वितीय वर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

निर्भया केस में दोषियों के वकील का कहना था कि दोषियों के पास अंतिम सांस तक अपने अधिकारों का उपयोग करने का हक है। हालांकि ये इजाजत भी उन्हे भारत के संविधान ने ही दी है। जेल नियमों के तहत एक अपराध में शामिल दोषियों को एक साथ सजा देने का प्रावधान है और इस नियम को बदला नहीं जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं । एक दृष्टि से दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद कानून के द्वारा मिली सजा के अमल में विलंब बिलकुल भी न्याय संगत नहीं लगता।

- **विवेक कुमार मौर्य,** एम०बी०बी०एस०-प्रथम वर्ष, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

निर्भया के अपराधियों से जुड़े विषय को हाल के दिनों में न्याय की कसौटी मान लिया गया है, जो कि न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। हम मान कर चल रहे हैं कि अगर फरवरी में फांसी नहीं हुई तो यह न्याय प्रणाली की विफलता होगी, जबकि सत्य यह है कि वास्तव में यह न्याय व्यवस्था की जीत है जो कोई भी निर्णय जन भावनाओं के आधार पर नहीं लेती है। इसलिए हमें जनभावनाओं के आधार इतना उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि निर्भया काण्ड के बाद क्या देश में बलात्कार की घटनाएँ नहीं हो रही हैं ? यदि हो रहीं है तो उन घटनाओं को रोकने के लिए संवैधानिक सुधारों की जरूरत है।

- **अंबेश सिंह,** एम०बी०ए० प्रथम वर्ष, सिमबाओसिस यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र

जिस प्रकार पिछले सात सालों से निर्भया के दोषियों को अभी तक उसके कुकृत्य की सजा नहीं मिल पाया है, ये चिंताजनक बात है। यह केवल निर्भया का ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई न होने का परिचय देता है। निर्भया के दोषियों की सजा का इंतजार पूरा देश कर रहा है लेकिन इंदिरा जय सिंह जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी संवेदनायें दोषियों के लिए प्रेषित कर, उस मां को जो पिछले सात साल से अपनी बेटी के इंसाफ हेतु लड़ाई लड़ रही है, उसे दोषियों को माफ करने की हिदायत देते हैं। इसके साथ ही मुजरिम का वकील निर्भया की मां को बोलता है कि अनंत काल तक फांसी टलेगी और संयोगवश फांसी की सजा टल भी गई। कल्पना कीजिए उस मां पर क्या गुजर रहा है जो विगत सात साल से अपने बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में मेरी राय है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में सुधार कर त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

- **गुंजन पंडिता,** छात्रा (डॉ. भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

परिषद गतिविधियां

जम्मू – कश्मीर : दीप प्रज्ज्वलित कर 'मदरसा विद्यार्थी सम्मेलन 2020' कार्यक्रम का उदघाटन करते अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर, मौलाना जाकिर हुसैन नक्शबंदी(चेयरमैन, सूफी फोरम जम्मू – कश्मीर), मुफ़्ती सकील रहमान, अभाविप प्रान्त अध्यक्ष ए. पी. सिंह व अन्य

अलीगढ: ब्रज प्रान्त द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र के साथ प्रतिभागी एवं मंचासीन अतिथि

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 FEBRUARY, 2020
DATE OF PUBLISHING: 8 FEBRUARY, 2020

POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI